

सब्र करने वाले को सब कुछ हासिल होता है

कश्मीर में दहशतगर्दी

कश्मीर में बीते तीन दिनों में तीन गैर कश्मीरियों को जिस तरह चुन-चुन कर हत्या की गई उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि घाटी में छिपे आतंकी दहशत फेलाने में तुल गए हैं। इस दहशतगर्दी का सिर कुचला ही जाना चाहिए और वह भी आनन-फानन। आतंकीयों ने जिन्हें अपना निशाना बनाया उनमें एक ट्रक ड्राइवर था, एक सेब व्यापारी और एक ईंट भट्टे में काम करने वाला मजदूर। आतंकीयों ने खास तौर पर सेब की खेप लाने गए लोगों को जिस तरह निशाना बनाया उसका मतलब यही है कि वे नहीं चाहते कि घाटी में सेब उगाने वाले किसानों का भला हो। ये तीन हत्याएं कश्मीरियत को कलंकित करने के साथ ही यह भी बताती हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर सक्रिय आतंकी किस तरह कश्मीरियों के लिए ही खतरा बन गए हैं। तीन निर्दोष-निहत्थे लोगों की हत्या के बाद कश्मीर में काम-धंधे के लिए गए अन्य लोगों में दहशत होना स्वाभाविक है। यदि उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं दिलाया गया तो वे कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। इससे सबसे अधिक अहित कश्मीर के लोगों का ही होगा। निःसंदेह एक ओर जहां यह जरूरी है कि पुलिस एवं सुरक्षा बल काम-धंधे की वजह से कश्मीर गए बाहरी लोगों का निशाना बना रहे आतंकीयों का सफाया करें वहीं यह भी आवश्यक है कि आम कश्मीरी जनता आतंकी तत्वों के खिलाफ खुलकर खड़ी हो। आम कश्मीरी जनता पाकिस्तानपरस्त कायर आतंकीयों और साथ ही उनके खुले-छिपे समर्थकों के खिलाफ मुखर हो, इसकी कोशिश सुरक्षा बलों के साथ-साथ कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी करनी चाहिए। ऐसा करके ही कश्मीरियत को जीवित किया जा सकता है।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि गैर कश्मीरी लोगों को मारने वाले आतंकीयों ने प्रतिबंधों में ढील का फायदा उठाया है। वे ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, इसकी न केवल तह तक जाना होगा, बल्कि आतंकीयों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्ती का भी परिचय देना होगा। ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंक के समर्थक मानवाधिकारों की फर्जी आड़ न लेने पाएं। सरकार और सुरक्षा बल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की बात करने वाले कई ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो वास्तव में अलगाव और आतंक के पिट्टू हैं। यही तत्व कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। उनकी ढिंढी का पता इससे चलता है कि वे खूंखार आतंकीयों को भी आम कश्मीरी नागरिकों की इस दस्त देने से बाज नहीं आते। यह जरूरी है कि भारत सरकार सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी मीडिया में सक्रिय ऐसे तत्वों को बेनकाब करने का काम करे।

2021 चुनाव की रणनीति

बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, परंतु वो पार्टियों में 2021 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने में होड़ सी लगी है। एक ओर तृणमूल तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए लोकसभा चुनाव में लगे झटके को भुला कर स्थिति मजबूत करने को अभी से मोहरे सजा रही है तो दूसरी ओर पहली बार बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा अपनी जमीन को और सख्त करते हुए तृणमूल को हर हाल में सत्ता से बाहर करने की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। भाजपा अब कोलकाता और आसपास के जिलों के साथ-साथ मुर्शिदाबदुल खसकर सीमावर्ती जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए विशेष अभियान छेड़ने की तैयारी की है। वहीं तृणमूल ने जनसंपर्क बढ़ाने और जनाधार को मजबूत करने के लिए 'दीदी के बोले' अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2021 विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। एक बाद एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जोड़ने की कोशिश में है। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोष ने स्वीकार किया है कि सूबे में भाजपा का प्रभाव काफी बढ़ा है। बावजूद इसके मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, वीरभूम जैसे जिलों में पार्टी अब भी कमजोर है। भाजपा राज्य नेतृत्व ने इन जिलों के संगठन को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ाएं, कार्यक्रम आयोजित करें और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं। इस समय भाजपा के बृथ स्तरीय संगठन का चुनाव चल रहा है। 79 हजार बृथ स्तरीय कमेटियों में से करीब 64 हजार बृथ स्तरीय कमेटियों का चुनाव हो चुका है। इस कमटी के जरिये ही भाजपा हर बृथ पर अपनी पहुंच को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं तृणमूल 'दीदी के बोले' अभियान के तहत 600 से अधिक ब्लॉक एवं नगर अध्यक्षों को राज्य के 2000 गांवों एवं वाडों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं वे सभी पार्टी सदस्यों के घर रात्रि भोजन करने के साथ-साथ बृथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। साथ ही पार्टी समर्थक के घर एक रात बिताएंगे। तृणमूल एवं भाजपा जहां एक के बाद एक रणनीति बन रही है तो दूसरी ओर माकपा एवं कांग्रेस में सन्नाट है।

जागरूकता की अदद जरूरत

मिताली जैन

हाल ही में कानपुर आइआईटी विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में शहर के तीन स्कूलों में 61 बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रस्त मिले। यहाँ सबसे चैकाने वाली बात यह थी कि इन बच्चों के माता-पिता, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अफसर और व्यवसायी हैं, लेकिन किसी भी अभिभावक ने बच्चों को न्यूरोलॉजिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ को नहीं दिखाया। यह अध्ययन जाहिर करता है कि आज के समय में अभिभावकों में जागरूकता का कितना अभाव है। इसकी कमी के कारण उनके बच्चों को कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे शारीरिक ही नहीं, बल्कि कई तरह की मानसिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। जब भी बच्चों में मानसिक समस्या की बात होती है तो सिर्फ तनाव, अवसाद या ऑस्टिज्म का ही नाम लिया जाता है, पर इसके अलावा भी एंपाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, सियोप्रेनिया जैसी कई मानसिक समस्याएं होती

अधिकांश माता-पिता में जागरूकता की कमी के कारण उनके बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं, लेकिन माता-पिता को इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। इसलिए वे बच्चों के गलत व्यवहार करने के कारणों की बात करें तो इन्हें कुछ भी उठा देते हैं। मानसिक समस्या होने पर जहां बच्चों को सही इलाज की जरूरत होती है, वहां पर उन्हें अपने माता-पिता की नाराजगी झेलनी पड़ती है, जिससे उनकी समस्या और अधिक बढ़ जाती है। जब तक अभिभावक को बच्चे की स्थिति के बारे में पता चलता है, तब तक स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी होती है। अगर बच्चों में बढ़ती मानसिक समस्याओं के कारणों की बात करें तो इन्हें इसके लिए एडवेंज वजहें जिम्मेदार है। इनमें सबसे पहली वजह है खानपान। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में सामाजिक और

गरीबों का जीवन बदलने वाले प्रयोग



विवेक कोल

वास्तविक जीवन में प्रयोग करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अभिजीत बनर्जी और दुपलो के साथ ऐसा नहीं है, उनके शोध प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं

वर्ष 2011 की बात है। अभिजीत बनर्जी मुंबई आए हुए थे और मुझे उनका साक्षात्कार करना था। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने मोरक्को से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग बयान किया। अपने मोरक्को दौर के दौरान बनर्जी जब एक गरीब आदमी से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि अगर तुम्हें थोड़े और पैसे मिलें तो तुम उन पैसे का क्या करोगे? उस आदमी ने कहा कि वह उन पैसे से भोजन खरीदेगा। इस पर बनर्जी ने उससे पूछा कि अगर और भी पैसा मिले तो वह उन पैसे का क्या करेगा? आदमी ने फिर जवाब दिया कि वह और भी भोजन खरीदेगा। बनर्जी को यह सुनकर काफी अजीब लगा, पर जब वह उस आदमी के घर पहुंचे तो हक्के-बक्के रह गए। उस आदमी के घर में टीवी और डीवीडी प्लेयर भी था। यह देखने के बाद बनर्जी ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त आहार नहीं है तो फिर टीवी कैसे है? इस पर उसने जवाब दिया कि जिंदगी में टीवी होना खाने से अधिक जरूरी है। बनर्जी के लिए यह काफी चौंकाने वाली बात थी। इस अनुभव से दो-चार होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी एस्थर दुपलो के साथ विश्व के कई देशों में भोजन के अधिकार पर कई प्रयोग किए। इसके अलावा उन्होंने बाल शैक्षिक सुधार की दिशा में भी काफी काम किया। उन्हें इन क्षेत्रों में काम के लिए ही मास्करल क्रैमर के साथ अर्थशास्त्र में इस साल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित

किया गया है। अधिकांश अर्थशास्त्री अपने काम के लिए प्रयोग आधारित दृष्टिकोण का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि वास्तविक जीवन में प्रयोग करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अभिजीत बनर्जी और दुपलो के साथ ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में उनके शोध प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। मोरक्को वाले उदहारण के आधार पर चीन में एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग की चर्चा बनर्जी ने उक्त साक्षात्कार में की थी। इसके बाद 2014 में मुंबई में हुए एक लिटरेचर फेस्टिवल में भी उन्होंने इसके बारे में काफी विस्तार से बताया। संयोग से मैं वहां मौजूद था। बनर्जी ने बताया कि हमने चीन में कुछ लोगों को सस्ते चावल खरीदने के लिए वाउचर दिए। हमारा अनुमान था कि इससे पोषण में सुधार होगा। चूंकि यह एक प्रयोग के रूप में किया गया था इसलिए कुछ लोगों को वाउचर दिए गए थे और कुछ को नहीं। इस प्रयोग का परिणाम उम्मीद से बहुत अलग निकला। आशा यह की जा रही थी कि लोगों का पोषण सुधरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बनर्जी ने बताया, वाउचर वाले लोग पोषण में बदतर निकले। दरअसल उन्हें लगा कि अब उनके पास वाउचर है सो वे पहले से ज्यादा अमीर हैं और अब उन्हें चावल खाने की जरूरत नहीं है। वे पोक, झींगा आदि खा सकते हैं। उन्होंने पोक और झींगा खरीदा और परिणामस्वरूप उनके शुद्ध कैलोरी ग्रहण में कमी हो गई। भले ही यह



अपवैत राजगुप्ता

बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, पर बनर्जी इसे पूरी तरह तर्कसंगत मानते हैं। उनका कहना है कि वे लोग आनंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। आनंद न केवल हमारे जीने के लिए, बल्कि हमारे भाग्य को नियंत्रित करने के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को लगता है कि उसे शेष जीवन दबबू होकर जीना होगा तो इसका मतलब है कि उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बनर्जी के अनुसार, चीन के वे लोग अपने पोषण में सुधार कर सकते थे या अगले दस दिनों के लिए थोड़ा बेहतर खा सकते थे, लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम भूल जाते हैं। दुनिया भर के विभिन्न देशों ने भोजन के अधिकार को इसी विचार के साथ लागू किया है कि अगर गरीब लोगों को रियायती भोजन दिया जाएगा तो उनके पोषण में सुधार होगा। जब खाद्य सुरक्षा नीतियां तैयार की जाती हैं तो उन्हें तैयार करने वाले जीवन के आनंद के बारे में नहीं सोचते। वे यह मानकर चलते हैं कि अगर

भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध कगया जाएगा तो लोग स्वाभाविक रूप से पोषण के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक बहुत ही सरल, किंतु गहरी बात है जो किसी प्रयोग से ही बाहर आ सकती थी। यह प्रयोग बनर्जी और दुपलो ने किया। ऐसे ही प्रयोग उन्होंने शैक्षिक क्षेत्र के क्षेत्र में भी किए और यह पाया कि भारत के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सुधार की काफी जरूरत है। उंची कक्षाओं के छात्र भी ठीक से पढ़-लिख नहीं पाते हैं। उन्हें बुनियादी गणित के सवाल हल करने में भी दिक्कत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकारी शिक्षकों के साथ एक प्रयोग किया। बनर्जी दंपती ने शिक्षकों से कहा कि छह हफ्ते तक वे केवल छात्रों के बुनियादी कौशल पर ध्यान दें। यदि वे पढ़ नहीं सकते तो उन्हें पढ़ना सिखाएं। यदि वे गणित में दक्ष नहीं तो उन्हें गणित सिखाएं। इन शिक्षकों को थोड़ा वजीफा और साथ ही कुछ दिनों का प्रशिक्षण भी दिया गया। छह सप्ताह के इस प्रयोग से

वक्त से पहले हासिल उपलब्धि

जिस देश में सरकारी योजनाएं दरी के लिए कुख्यात हों वहां समय से पहले किसी योजना का लक्ष्य पूरा होना नई और अनोखी बात है। इस मामले में सबसे उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना। इस योजना के तहत मार्च 2020 तक आठ करोड़ गैस सिलेंडर देने का लक्ष्य वच किया गया था, लेकिन उसे बीते महीने यानी निर्धारित समय से सात माह पहले हासिल कर लिया गया। इस योजना के साथ ही सरकार हर गांव तक बिजली पहुंचाने और हर घर को शौचालय सुलभ कराने में भी कामयाब रही है। चूंकि मोदी सरकार की इन योजनाओं का लक्ष्य चुनावी राजनीति न होकर आम आदमी का सशक्तिकरण है इसलिए चुनावी वीतने के बाद भी उनके क्रियान्वयन पर पहले जैसा ही जोर दिया जा रहा है। अभी तक सरकारों आम तौर पर चुनावों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाती रही हैं। इसीलिए चुनावी वीतने ही उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती थी। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी, नैकरशाही की शिथिलता और भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण सरकारी योजनाओं के अपेक्षित लाभ हासिल नहीं होते थे। वास्तव में इसी कारण जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों उन्मूलन का कारगर हथियार नहीं बन पाईं। इसके विपरीत मोदी सरकार ने समाज के वंचित तबकों को हर तरह से सशक्त बनाने का काम किया। गरीबों को बिजली, सड़क, पक्के मकान, शौचालय, रसोई गैस जैसे मूलभूत सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के मिलीं, जिनके लिए सरकारें आम आदमी को दशकों से ख्वाब दिखा रही थीं। जैसे-जैसे मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ प्रामाणिक इलाकों और वंचित तबकों तक पहुंचा वैसे-वैसे इन क्षेत्रों और समुदायों में भाजपा की पैठ बढ़ी। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्वला योजना का उल्लेख इसीलिए बार-बार होता है, क्योंकि इससे करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी तो मिली ही, उनके समय की कबत भी हुई। चूल्हे में भोजन पकाने में महिलाओं को बहुत अधिक झुझ के साथ समय भी खपाना पड़ता था। अब उन्हें कहीं कम समय देना पड़ता है। शेष समय का उपयोग वे ऐसे कार्यों में करती हैं जिनसे उनका जीवन सुधरे।



रमेश कुमार दुवे

उज्वला के तहत मार्च 2020 तक आठ करोड़ गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करना बड़ी बात है



देश में परंपरागत चूल्हों से होने वाले प्रदूषण से हर साल पांच लाख महिलाओं की मौत हो जाती थी। विशेषज्ञों के मुताबिक रसोई में खुली आग के धुएं में एक घंटे बैठने का मतलब चार सौ सिगरेट के बराबर धुआं सूंघना है। 2014 में वलरड इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया में सबसे अधिक जैव ईंधन पर निर्भर आबादी विकासशील एशिया में है। अकेले भारत में 70 करोड़ लोग परंपरागत ईंधन (लकड़ी, गोबर आदि) से खाना बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ऐसे प्रदूषण से हर साल 20 लाख लोगों की अकाल मौत होती है जिसमें करीब 44 फीसद बच्चे हैं। वहीं बड़े लोगों में 60 फीसद महिलाएं। इस तरह के प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में चली जाती हैं। यह संख्या हर साल मलेरिया से होने वाली कुल मौतों से ज्यादा है, लेकिन विदर्भना यह है कि जल मलेरिया की रोकथाम के लिए बचाव से लेकर इलाज तक हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं वहीं रसोईघर के खरते को काबू करने के लिए बहुत कम प्रयास हुए। आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। देश में एलपीजी वितरण की शुरुआत 1955 में हुई थी और 2014 तक अर्धोत् साठ घंटे के दौरान सिर्फ 13 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया जा सका। वहीं एलपीजी का दायरा शहरी एवं कस्बाई इलाकों तथा गांवों के समृद्ध वर्ग तक सिमटा रहा। स्पष्ट है सरकारी उदासीनता के चलते चूल्हे के धुएं से हर साल लाखों लोग बीमार पड़कर परीब बनते रहे। गरीबों को चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति दिलाने की पहली ठोस पहल मई 2016 में 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' के तहत हुई। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पांच करोड़ परिवारों को मार्च 2019 तक

एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। बाद में लक्ष्य को बढ़ा करते हुए मार्च 2020 तक आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। शुरू में इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिल रहा था जो 2011 की गणना के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे थे। आगे चलकर इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें सभी अनुसूचित जाति-जनजाति परिवार, वनवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, द्वीपों, चाय बागानों में रहने वालों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अंत्येदो योजना के लाभार्थियों को भी शामिल कर लिया गया। राजनीतिक इच्छाशक्ति और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के कारण उज्वला योजना में लक्ष्य की तुलना में अधिक कनेक्शन बांटे गए। इसका नतीजा यह रहा कि आठ करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य वक्त से पहले हासिल हो गया। यदि कुल गैस कनेक्शनों को देखें तो यह आंकड़ा 10 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा। अब तक देश की 95 प्रतिशत आबादी तक रसोई गैस पहुंच चुकी है और हर रोज 69000 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर नए गैस कनेक्शन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर जैसे पिछड़े राज्यों में जारी हुए जहां स्पष्ट ईंधन की कमी बहुत कम रही। उज्वला योजना के कुल लाभार्थियों में 48 प्रतिशत अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंध रखते हैं। स्पष्ट है कि उज्वला योजना करोड़ों गरीबों के सशक्तिकरण का कारगर हथियार साबित हुई है। रसोई गैस की देशव्यापी पहुंच के बाद एक बड़ी चुनौती यह आ रही है कि जहां सामान्य उपभोक्ता प्रति वयं औसतन सात सिलेंडर गैस भरवाते हैं वहीं उज्वला योजना के लाभार्थी औसतन तीन सिलेंडर ही भरवाते हैं। बड़े सिलेंडर की कीमत अधिक होने के कारण बीपीएल परिवारों द्वारा कम संख्या में सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए मोदी सरकार पांच किलो के छोटे सिलेंडर आवांठित कर रही है। यह जरूरी है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन छोटे सिलेंडरों का उपयोग बढ़े, क्योंकि ऐसा करके ही कुपोषण की समस्या का सामना किया जा सकता है। चूंकि अब सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में अधिक अंतर नहीं रह गया है इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या रसोई गैस सब्सिडी खत्म करने का समय आ गया है? (लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं) response@jagran.com



ऊर्जा

आंतरिक प्रकाश

विश्व के हर धर्म ने किसी न किसी रूप में मन की अवस्था की बात की है। बाह्य परिस्थितियां उसकी सोच और व्यवहार को संचालित करती रहती हैं। किसी दूसरे देश में भूकंप आता है तो वह कर्णामा से भर उठता है। किसी अपरिचित की उपलब्धि पर वह हर्ष से भर जाता है। उसे अहसास भी नहीं होता कि उसके मन के अंदर भी निरंतर कुछ न कुछ घटित हो रहा है। उसके पास दृष्टि ही नहीं है अपने मन में देखने की। उसकी आयु निरंतर व्यतीत होती जा रही है। उसके दुर्लभ मानव जीवन का अवसर निरंतर संकुचित होता जा रहा है। उसका मन दुख से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। उसे मन का यह दुख दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंदर तो माया, मोह और विकारों का अंधकार व्याप्त है। माया और विकार उसे लूट रहे हैं, किंतु वह अनभिज्ञ है। यह परमात्मा के विश्वास को तोड़ना और जीवन हार जानने जैसा है। अंधेरा कभी भी स्वागतयोग्य नहीं है। बाहर तो उजाले के लिए बड़े-बड़े बिजली घर बना लिए गए, नित नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं, किंतु मन में वैसे ही अंधेरा है। मन में उजाले का अभाव है प्रति अट्ट आस्था और श्रेष्ठ जीवन गुणों के बिजली घर नहीं लगाए जाते तब तक जीवन उद्देश्य नहीं देखने को मिलेगा। यह पता तो चले कि कहाँ और कैसे जाना है। जीवन उपभोग के लिए नहीं उपयोग के लिए मिला है। मोह, माया और विकारों के अंधेरे में तो मनुष्य ने न जाने कितनी सदियां गुजार दी हैं और अभी भी आवामामन के चक्र में फंसा हुआ है। मनुष्य का जन्म ऐसा अवसर है उस अंधेरे से आजाद होने का, अपने जन्म-जन्मों के पाप धोकर पुण्य कमाने और परमात्मा की कृपा पाने का, ताकि मुक्ति प्राप्त हो सके। यह आस्था और गुणों के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। मन के अंदर के जीवन लक्ष्य के बीज को आस्था की हवा, गुणों का पानी और संकल्प का प्रकाश दें और उसे अंकुरित, पल्लवित होने दें। इस बार उजाले का पर्व, मन को प्रकाशित करने के लिए मनाएं। आंतरिक प्रकाश के बिना बाहरी प्रकाश व्यर्थ है। डॉ. सत्येंद्र पाव सिंह

सही दिशा में भारत की कूटनीति

भारत के खिलाफ उभरता नया गठजोड़ शीर्षक से लिखे लेख में ब्रिगेडियर आरपी सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को तुर्की, मलेशिया और चीन से मिले समर्थन और उससे जुड़े विविध पहलुओं का सांगोपांग वर्णन किया है। जहां तक मलेशिया की बात है, उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने उससे होने वाले आयातों में कमी लाने के संकेत दिए हैं। निशाना सही जगह पर लगता हुआ दिख भी रहा है। मलेशिया ने भारत से आयात बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तुर्की की बात करें तो उसके साइप्रस और ग्रीस के साथ ऐतिहासिक रूप से बेहद खराब रिश्ते हैं, खासकर जुलाई 1974 में उसके द्वारा बलपूर्वक साइप्रस के उत्तरी क्षेत्र को हड़प लेने के पश्चात। आर्मनिया के साथ भी उसका कोई औपचारिक संबंध नहीं है, विशेषकर मार्च 2018 में दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने वाले प्रोटोकॉल (2008) को आर्मनिया द्वारा निरस्त कर देने के बाद। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की द्वारा कश्मीर का राग अलापने के बाद मोदी ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मनिया के राष्ट्र प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें एक सख्त कूटनीतिक संकेत दे दिया है। इधर चीन को साधने के लिए भी यह आवश्यक है कि भारत उस पर युक्तिसंगत आर्थिक-राजनीतिक दबाव लगाता बनाए रखे। चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग के हालिया भारत दौरे में उनके द्वारा कश्मीर के मुद्दे को उठाने से परहेज को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है। मोदी सरकार ने अपने काल में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामलों में भारत की परंपरागत सुरक्षात्मक नीति में यथोचित संशोधन कर उसे भारत के हित में अधिक प्रासंगिक बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। चंद्र कुमार, देवघर

मेलबाक्स

भारत में कुपोषण

दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों में भारत का नाम आता है। भारत के अंदर इस अवस्था के लिए सिर्फ हम प्रशासन को ही जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा के बाद सबसे ज्यादा खाना भारत में बर्बाद होता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक विकसित देश है और हम एक विकासशील राष्ट्र। अपने देश में उत्पादन होने वाला 40 प्रतिशत भोजन बर्बाद हो जाता है। यह कुव्यवस्था का परिचायक है। हम अगर चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को पोषिक आहार मिले, यह भी सुनिश्चित करना होगा। विजय किशोर तिवारी, शिक्षक, नई दिल्ली

धैर्य की आवश्यकता

दैनिक जागरण के 17 अक्टूबर के अंक में संपादकीय, फैसले की प्रतीक्षा, पढ़ा। अयोध्या प्रकरण में सुप्रिम कोर्ट का भी फैसला आए सभी को उसका समान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उचित होगा कि दोनों पक्ष इसके लिए माहौल बनाएं कि जो भी फैसला आए उसे सभी स्वीकार करें। भले ही दुनिया की नजर में यह एक जमीनी टुकड़े की लड़ाई हो, लेकिन ये भी सच है कि यह मामला आस्था से भी जुड़ा है। साक्ष्य जिसके पक्ष में होंगे फैसला उसी के पक्ष में जाएगा। इसमें दोनों पक्षों को अत्यंत धैर्य रखने की आवश्यकता है। चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

प्रदूषण की रोकथाम

देश में बढ़ता प्रदूषण भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। पूरे देश में जलवायु जहरीली होने लगी है। जिस तरह कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियां अपराधों की रोकथाम के लिए काम करती हैं उसी तरह सभी राज्यों को भी जिम्मेदारी लेकर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। आचार्य राम कुमार बबल, प्रभारी पर्यावरण सचेतक, पलवल

वदलते वक्त को समझें

कभी भारतीय राजनीति की धुरी रही कांग्रेस आज जिस हाल में है उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक प्रभाव विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कांग्रेस अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं कर पा रही है। पार्टी छोड़ने वाली की तादात रोज बढ़ती जा रही है। कांग्रेस को खुद कांग्रेसी ही पुनर्जीवित कर सकते हैं। पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक को बदलते वक्त को समझना होगा। वृजेश माथुर, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सांद्र आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं। अपने पत्र इस पते पर भेजें: दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा ई-मेल: mailbox@jagran.com